गुरा सिंह

बनाम

राजस्थान का राज्य

6 दिसंबर, 2000

[के. टी. थॉमस और आर. पी. सेठी जेजे.]

दंड संहिता, 1872–धारा 302–दोषसिद्धि–अभियोजन वाद अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति पर आधारित–सभी गवाह अपीलार्थी से निकटता से संबंधित हैं–घटना के तुरंत बाद किया गया संस्वीकृति जो किसी भी असम्यक असर, उत्पीड़न या दबाव के तहत प्राप्त नहीं–मुख्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए–अभियोजन साक्षी द्वारा स्वैच्छिक रूप से किए गए प्रकटीकरण कथन के पश्चात कारित अपराध में प्रयुक्त हथियार एवं अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी–धारित, अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि समुचित है।

अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति–गवाह केवल घटना के बाद के विवरण पर सहमत नहीं था–गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया–न्यायालय ने अभियोजक को गवाह की प्रतिपरीक्षा करने के लिए अनुमति दी–धारित, गवाह पक्षद्रोही नहीं हुए–इसके अलावा, गवाह को गलत तरीके से प्रतिपरीक्षा हेतु साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 154 के तहत अनुमति दी गई थी।

साक्ष्य अधिनियम, 1872–धारा 27 और 45–चादर और अन्य वस्तुओं की बरामदगी–अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के आधार पर– चादर और अन्य वस्तु रक्त से सना हुआ था–समय बीतने के कारण सीरोलॉजिस्ट रक्त की उत्पत्ति का निर्धारण करने में विफल रहा–चादर और अन्य वस्तुओं पर रक्त के दाग के आयामों का उल्लेख नहीं किया गया–धारित, अभियुक्त किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

अपीलार्थी को सत्र न्यायालय में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत विचारण हेतु दौरासुपुर्द किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति पर आधारित था।अभियोजन पक्ष के गवाहों का परीक्षण करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपीलार्थी ने अपील की याचिका दायर की। यह तर्क दिया गया कि चूंकि मुख्य गवाह पक्षद्रोही हो गए, इसलिए उनकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि उचित नहीं थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया–

1.1 . न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति, यदि सत्य और स्वैच्छिक है, तो अदालत द्वारा कथित अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। साक्ष्य के रूप में न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति की अंतर्निहित कमजोरी के बावजूद, जब यह दिखाया जाता है कि ऐसी स्वीकारोक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने की गई थी जिसके पास गलत बयान देने का कोई कारण नहीं है और यह उन परिस्थितियों में किया गया है जो बयान का समर्थन करते हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। [412 – ई]

राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य, [1954] एससीआर 1098 ; मगहर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1975) एस. सी. 1320; नारायण सिंह बनाम एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1985) एस. सी. 1678; किशोर चंद बनाम एच. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1990) एस. सी. 2140; बलदेव राज बनाम हरियाणा राज्य, ए. आई. आर. (1991) एस. सी. 37; प्यारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1977) एससी 2274 और मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे और अन्य, जे. टी. (1992) 3 एस. सी. 270, संदर्भित।

1.2 . वर्तमान मामले में, PW5 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था और अपीलकर्ता ने PW7 से न्यायेतर स्वीकारोक्ति की है जब वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उसके द्वारा की गई कोई भी स्वीकारोक्ति साक्ष्य में अग्राह्य है। इस प्रकार यह तय करने के प्रयोजन के लिए की अपीलकर्ता ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति की थी या नही उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। समय, रीति और उपस्थित परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि अपीलकर्ता ने बिना किसी डर, पक्षपात या दबाव के इस गवाह के समक्ष स्वैच्छिक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी। [414 – बी, सी, डी]

1.3 . अभियोजन पक्ष का गवाह केवल सरकारी वकील द्वारा घटना के बाद दिए गए ब्यौरे से सहमत नहीं था। इसलिए, सरकारी वकील के लिए यह घोषित करना अपर्याप्त था कि गवाह ने पलटवार किया और अभियोजन पक्ष के प्रति पूरी तरह से पक्षद्रोही हो गया। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट द्वारा कथित तौर पर उसके पक्षद्रोही होने के आधार पर जिरह करने की अनुमति गलत तरीके से दी गई थी। इससे भी अधिक, जिरह के लिए दी गई और उपयोग की गई अनुमति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय तक ही सीमित थी, न कि उसके बयान के तथ्य के संबंध में जहां तक यह अतिरिक्त न्यायिक बयान देने से संबंधित है। [418 – डी; 414–जी]

1.4 . पीडब्लू 5 और 7 की गवाही के अभाव में भी यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि अपीलकर्ता ने अनुचित प्रभाव, दबाव, वादे या प्रलोभन के बिना पीडब्लू 2 और 6 के समक्ष स्वैच्छिक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी और इन गवाही के आधार पर दोषसिद्धि उचित है। गवाहों का अपीलकर्ता से गहरा संबंध है, जिसके बारे में सामान्य परिस्थितियों में, उसने मदद, सुरक्षा और सुरक्षा की उम्मीद

करते हुए बयान दिया होगा। यह स्वीकारोक्ति घटना के तुरंत बाद की गई थी और किसी अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न या दबाव के तहत नहीं ली गई थी। [413 – एफ]

1.5 . सीरोलॉजिस्ट और रासायनिक परीक्षक ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के परिणामस्वरूप जब्त की गई चादर मानव रक्त से सना हुआ था। समय बीतने के साथ रक्त का वर्गीकरण निर्धारित नहीं किया जा सका; इस प्रकार, किसी भी लाभ का दावा करने के लिए आरोपी को कोई बोनस नहीं दिया जाता है। इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ परिस्थिति को संदेह से परे साबित मानना अदालत के लिए उचित है। [421–डी, ई]

प्रभु बाबाजी नवल बनाम बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 51; राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1963) एससी 74; शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1981] 2 एस. सी. आर. 384 और कंस बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. (1987) एस. सी. 1507, उद्धृत किया गया है।

राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य, [1999] 3 एस. सी. सी. 507, पर आधारित।

1.6 . खून के धब्बों के आयामों का उल्लेख न करने पर केवल संदेह पैदा करना ही आरोपी को उचित संदेह का लाभ देने के लिए पर्याप्त नहीं है। रक्त के धब्बों के आयामों का उल्लेख न करना उन मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है जहां अभियुक्त बचाव की गुहार लगाता है या अपराध के कमीशन में उसे गलत तरीके से शामिल करने के लिए साक्ष्य गढ़ने के अभियोजन पक्ष की दुर्भावना का आरोप लगाता है। [422–ई, एफ]

कंस बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. (1987) एस. सी. 1507, विशिष्ट।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारिता : आपराधिक अपील सं० 1184 /1998

राजस्थान उच्च न्यायालय के D.B.Crl. A. No. 299 of 1978 में दिनांक 17.1.97 को पारित निर्णय और आदेश से

अपीलार्थियों की ओर से डूंगर सिंह, वी. जे. फ्रांसिस, पी. आई. जोस और जेनिस फ्रांसिस।

सुशील कुमार जैन ए. मिश्रा और ए. पी. धमीजा प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायामूर्ति सेठी के द्वारा दिया गया था।

पुलिस स्टेशन करणपुर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अंतर्गत एक शांत और छोटे से गांव में 7 जुलाई, 1976 की सुबह एक असामान्य रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी, जिसके

परिणामस्वरूप पितृहत्या का अपराध हुआ। हत्यारा अपीलकर्ता और पीड़ित उसका अभागा पिता है। मामूली सी बात पर इतना जघन्य अपराध कर दिया गया, जिसकी शुरुआत पिता–पुत्र के बीच विवाद से हुई। पिता ने अपीलकर्ता को उसकी फिजूलखर्ची की याद दिलाई जो उसके बेटे को पसंद नहीं थी, उसने मृतक को जमीन पर गिरा दिया और कस्सी (खंजर) से उसकी खोपड़ी तोड़ दी। अगली सुबह अपीलकर्ता जरनैल सिंह (पीडब्ल्यू 2) के पास गया और अपराध के बारे में स्वीकार किया और बताया कि किस तरह से चोटें पहुंचाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप मृतक भजन सिंह की मृत्यु हो गई। जरनैल सिंह (पीडब्लू2) की कंपनी में, अपीलकर्ता ने बिल्लोर सिंह (पीडब्लू5), निरंजन सिंह (पीडब्लू6) और जोगिंदर सिंह (पीडब्लू7) से संपर्क किया और उनके सामने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की और उनसे उसकी मदद करने का अनुरोध किया। इसके बाद जरनैल सिंह (पीडब्लू2) और बिल्लोर सिंह (पीडब्लू5) ने अमर सिंह, पंच को बुलाया। जरनैल सिंह ने दोपहर 12.30 बजे पुलिस स्टेशन, करणपुर, जो घटना स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) दर्ज कराई। अपीलकर्ता को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने प्रकटीकरण अभिकथन दिया (प्रदर्श पी21) दिया जिसके परिणामस्वरूप अपराध का हथियार कस्सी (प्रदर्श पी19) बरामद किया गया। पुनः 12.7.1976 को अपीलकर्ता ने एक और प्रकटीकरण बयान दिया जिसके परिणामस्वरूप खून से सना हुआ एक चादर (प्रदर्श पी–12) बरामद किया गया (प्रदर्श पी–22)।

अपीलकर्ता को धारा 302 आई०पी०सी० के तहत अपना मुकदमा चलाने के लिए दिनांक 10.2.1977 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाहों को पेश करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले दिनांक 9.8.1978 के तहत अपीलकर्ता को दोषी पाया और धारा 302 आई.पी.सी. के तहत दोषसिद्ध ठहराया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने इस अपील में दिए गए फैसले के तहत खारिज कर दिया था।

अपीलकर्ता की ओर से उसके वकील द्वारा उठाए गए तर्कों की सराहना करने से पहले, उस युक्ति को नोट करना उपयोगी है जिसके तहत अपराध किया गया था। मृतक और अपीलकर्ता के साथ गवाहों के संबंध पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अपराध के दुर्भाग्यपूर्ण पीडित भजन सिंह की दो पत्नियाँ थीं। अपीलकर्ता दूसरी पत्नी सुश्री हर कौर का बेटा है, जिसकी पहले कपूर सिंह नामक व्यक्ति से शादी हुई थी। जोगिंदर सिंह (पीडब्लू 7) पीड़िता की पहली पत्नी का बेटा है और निरंजन सिंह (पीडब्लू 6) दामाद है। मृतक भजन सिंह का एक भाई था, जिसका नाम रूड़ सिंह है, जिसका बेटा जरनैल सिंह (पीडब्लू2) है। मृतक भजन सिंह के पास बडोपल (राजस्थान) में 105 बीघा जमीन थी, जहां वह अपीलकर्ता के साथ रहता था। जोगिंदर सिंह (पीडब्लू 7) पंजाब में रह रहा था जहां वह भजन सिंह और उसके परिवार की 40 एकड़ जमीन की देखभाल करता था। बताया जाता है कि घटना से कुछ दिन पहले भजन सिंह और अपीलकर्ता के बीच अपनी भाभी की शादी और हैंडपंप लगवाने में आरोपी द्वारा

किए गए खर्च को लेकर कुछ विवाद हुआ था। घटना के दिन, जिसके कारण मृतक की हत्या हुई, उसी मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई, जिसे अपीलकर्ता ने गंभीरता से नहीं लिया, और 7 जुलाई, 1976 को सुबह 01 बजे कस्सी से हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। माना कि कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से अपीलकर्ता के न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति के साथ–साथ नए तथ्यों की खोज पर आधारित है, जिससे अपराध के हथियार और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी हुई है। अभियोजन ने उस मकसद के अस्तित्व पर भी भरोसा किया है जिसने मृतक को अपराध करने के लिए क्रोधित किया। हालाँकि, यह निर्विवाद है कि भजन सिंह की मृत्यु हत्या थी और जिस तरह से उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोटें पहुंचाई गईं , वह धारा 300 आईपीसी के अर्थ के तहत हत्या के अपराध को दर्शाता है, उसमें निर्दिष्ट किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता।

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर की गई न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति को सभी उचित संदेहों से परे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है। उनके अनुसार अपीलकर्ता को मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को हड़पने के परोक्ष उद्देश्य से अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा गलत तरीके से उसके पिता की हत्या के आरोप में फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि मुख्य गवाह मुकर गए हैं , इसलिए उनकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि उचित नहीं है।

कानून की यह स्थापित स्थिति है कि न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति, यदि सत्य और स्वैच्छिक है, तो अदालत द्वारा कथित अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। साक्ष्य के रूप में न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति की अंतर्निहित कमजोरी के बावजूद, जब यह दिखाया जाता है कि ऐसी स्वीकारोक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने की गई थी जिसके पास गलत बयान देने का कोई कारण नहीं है और यह उन परिस्थितियों में किया गया है जो बयान का समर्थन करते हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य [1954 एससीआर 1098] में पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए , इस न्यायालय ने फिर से मगहर सिंह बनाम पंजाब राज्य [एआईआर 1975 एससी 1320] में माना कि अभियुक्त द्वारा गवाहों के सामने की गई न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति को हमेशा दागदार साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे साक्ष्यों की पुष्टि केवल अत्यधिक सावधानी से ही आवश्यक है। यदि अदालत उस गवाह पर विश्वास करती है जिसके सामने स्वीकारोक्ति की गई है और संतुष्ट है कि स्वीकारोक्ति सच थी और स्वेच्छा से की गई थी , तो दोषसिद्धि अकेले ऐसे सबूतों पर स्थापित की जा सकती है। नारायण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में । [एआईआर 1985 एससी 1678] इस न्यायालय ने आगाह किया कि अदालत इस धारणा के साथ आपराधिक मामले की सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार नहीं है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति हमेशा एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होता है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, संस्वीकृति के समय और ऐसे संस्वीकृति के पक्ष में बोलने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। गैर–न्यायिक स्वीकारोक्ति को वापस लेना, जो कि आपराधिक मामलों में

एक सामान्य घटना है, इस तरह की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करेगा। किशोर चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में । [एआईआर 1990 एससी 2140] इस न्यायालय ने माना कि एक स्पष्ट अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति में उच्च संभावित मूल्य बल होता है क्योंकि यह उस व्यक्ति से निकलता है जिसने अपराध किया है और साक्ष्य में स्वीकार्य है, बशर्ते यह संदेह और किसी भी झूठ से मुक्त हो। हालाँकि, कथित स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने से पहले, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि यह स्वैच्छिक है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत परिकल्पित प्रलोभन, धमकी या वादे का परिणाम नहीं है या साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 को दरकिनार करने के लिए संदिग्ध परिस्थितियों में लाया गया था । न्यायालय को यह पता लगाने के लिए आसपास की परिस्थितियों पर गौर करने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह की स्वीकारोक्ति किसी अनुचित या संपार्श्विक विचार या कानून के उल्लंघन से प्रेरित नहीं है जो यह बताती है कि यह सच नहीं हो सकता है। सभी प्रासंगिक परिस्थितियों जैसे कि वह व्यक्ति जिससे स्वीकारोक्ति की गई है, इसे करने का समय और स्थान, जिन परिस्थितियों में यह किया गया था, उनकी जांच की जानी चाहिए। इसी आशय का निर्णय बलदेव राज बनाम हरियाणा राज्य [एआईआर 1991 एससी 37] में दिया गया है। पियारा सिंह बनाम पंजाब राज्य [एआईआर 1977 एससी 2274] में फैसले का उल्लेख करने के बाद, मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे और अन्य [जेटी] के मामले में। 1992 (3) एससी 270] न्यायालय ने माना कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति जो उत्पीडन,लाभ के वादे या झूठी आशा से प्राप्त नहीं की जाती है और प्रकृति में पूर्ण और स्वैच्छिक है, उसे पुष्टि के बिना भी सजा का आधार बनाया जा सकता है। मौजूदा मामले में अपीलकर्ता द्वारा की गई न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति को साक्षी संख्या 2, 5, 6 और 7 की गवाही से साबित करने की मांग की गई। जैसा कि पहले देखा गया है, उपरोक्त सभी गवाह अपीलकर्ता से निकटता से संबंधित हैं, जिसके तहत, सामान्य परिस्थितियों में, उसने मदद, सुरक्षा और सुरक्षित होने की उम्मीद जताई होगी। यह स्वीकारोक्ति घटना के तुरंत बाद की गई है और यह आरोप नहीं लगाया गया है कि इसे किसी अनुचित प्रभाव, दबाव या उत्पीडन के तहत प्राप्त किया गया है। हालाँकि अपीलकर्ता को गवाहों से समर्थन की उम्मीद थी, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि उनमें से किसी ने भी घटना के संबंध में सच्चा बयान देने की स्थिति में उसका पक्ष लेने का वादा नहीं किया था। साक्षी संख्या 6 और 7 द्वारा मृतक की संपत्ति को हड़पने के सुझाव के अलावा, कोई अन्य सुझाव नहीं है जो यह दिखा सके कि उनके साक्ष्य दागी हैं और अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष पर आपत्ति जताते हुए, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि साक्षी संख्या 2, 5 और 7 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है और साक्षी संख्या 6 एक हितबद्ध साक्षी है, इसलिए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति जो अपीलकर्ता के मत्थे मढ़ी गई है को अभियोजन द्वारा एक तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

यह सच है कि PW5 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है और अपीलकर्ता ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति की है या नहीं, यह तय करने के लिए उसकी गवाही पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता

है। इसी तरह, PW7 जोगिंदर सिंह का बयान जहां तक अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति करने का संदर्भ देता है, साक्ष्य में अग्राह्य है क्योंकि जब तक यह गवाह घटना स्थल पर पहुंचा, तब तक अपीलकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद उसके द्वारा की गई कोई भी स्वीकारोक्ति साक्ष्य में अग्राह्य है। यह साक्ष्य में है कि अपीलकर्ता को गांव में जोगिंदर सिंह (PW7) के आने से पहले गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, निरंजन सिंह (PW6) के विश्वसनीय सबूत हैं जिन पर नीचे की दोनों अदालतों ने विश्वास किया है और हमें उपरोक्त निष्कर्षों से असहमत होने के लिए विश्वस्त नहीं किया गया है। हम इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं कि PW6 ने कथित तौर पर अपीलकर्ता को मृतक भजन सिंह की संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित करने के लिए बयान दिया था। समय, रीति और उपस्थित परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि अपीलकर्ता ने बिना किसी डर, पक्षपात या दबाव के इस गवाह के समक्ष स्वैच्छिक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी।

PW2 की गवाही पर इस आधार पर आक्रमण किया गया है कि चूंकि उसे कथित तौर पर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था, उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने PW2 के बयान की जांच की है और पाया है कि उसने सभी भौतिक विवरणों में अभियोजन के मामले का पूरा समर्थन किया था। अपने मुख्य परीक्षण में गवाह ने न्यायेतर संस्वीकृति देने के तरीके को स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहा है कि वह लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, अन्य लोगों के साथ, दोपहर लगभग 12.00 बजे पुलिस स्टेशन करणपुर पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन थाना पुलिस ने यह कहकर मामला दर्ज नहीं किया कि यह पारिवारिक मामला है और गांव में पूछताछ करने के बाद ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इस तरह के बयान को पहले की गवाही से अलग पाते हुए, लोक अभियोजक ने अदालत से गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने और "इस आधार पर उससे जिरह करने की अनुमति मांगी कि उसने यह नहीं कहा था कि प्रदर्श पी–2 तुरंत पंजीकृत नहीं किया गया था।" विचारण न्यायालय ने लोक अभियोजक को उस सीमा तक जिरह करने की अनुमति देकर अनुग्रह किया। लोक अभियोजक द्वारा जिरह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तक ही सीमित है, न कि उसके बयान के तथ्य के संबंध में, जहां तक यह अपीलकर्ता द्वारा न्यायेतर स्वीकारोक्ति करने से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष इस तथ्य से भी अवगत है कि लोक अभियोजक ने एक सीमित सीमा तक गवाह से जिरह करने की अनुमति मांगी थी। अपीलकर्ता द्वारा न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में गवाह से लंबी और विस्तृत जिरह की गई। विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने यह मानने के लिए उसकी गवाही पर सही ढंग से भरोसा किया कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से उपरोक्त गवाह के सामने अतिरिक्त न्यायिक बयान दिया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षद्रोही घोषित किए गए गवाह की गवाही पर उसके प्रभाव के बारे में गलत धारणा है। यह एक गलत धारणा है कि केवल इसलिए कि एक गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है, उसके पूरे अभिसाक्ष्य को बाहर कर दिया जाना चाहिए या विचार के अयोग्य बना दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य AIR (1976) SC 202 में धारित किया है

कि केवल इसलिए कि न्यायालय ने लोक अभियोजक को अपने ही गवाह को पक्षद्रोही गवाह बताते हुए उससे जिरह करने की अनुमति दे दी, इससे उसके अभिसाक्ष्य पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते। विचारण में साक्ष्य ग्राह्य रहता है और ऐसे गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि का आधार बनाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। रवीन्द्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य AIR 1977 SC 170 में यह संप्रेक्षित किया है कि जिरह की अनुमति देने से गवाह की साख के प्रतिकूल कुछ भी तय नहीं होता है और केवल पक्षद्रोही घोषित होने से गवाह अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। केवल इस आधार पर उसकी पूरी गवाही को विचार से बाहर नहीं किया जा सकता। एक आपराधिक विचारण में, जहां अभियोजन पक्ष के गवाह से न्यायालय की अनुमति से उस पक्ष द्वारा जिसने साक्ष्य के लिए उसे बुलाया है जिरह की जाती है और उसका खंडन किया जाता है, सामान्य नियम के रूप में, इसे पूरी तरह से अभिलेख से बाहर नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह विचार करना तथ्य की अदालत का काम है कि क्या इस तरह की जिरह और विरोधाभास के परिणामस्वरूप गवाह कलंकित हो गया है या उसकी गवाही के किसी भी हिस्से के संबंध में अभी भी उस पर विश्वास किया जा सकता है। उपयुक्त मामलों में न्यायालय ऐसे गवाह की गवाही के हिस्से पर भरोसा कर सकती है, यदि बयान का वह हिस्सा विश्वसनीय पाया जाता है।

"पक्षद्रोही", "प्रतिकूल" या "मुखालिफ" गवाह शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम से अजनबी हैं। शब्द "पक्षद्रोही गवाह", "प्रतिकूल गवाह", " मुखालिफ गवाह", "अनिच्छुक गवाह" सभी अंग्रेजी विधि की शब्दावली हैं। गवाह को बुलाने वाले पक्ष को जिरह के लिए अनुमति न देने के नियम को "पक्षद्रोही गवाह और प्रतिकूल गवाह" की शब्दावली को विकसित करके सामान्य विधि के तहत शिथिल कर दिया गया है। सामान्य विधि के तहत एक पक्षद्रोही गवाह का वर्णन उस व्यक्ति के रूप में किया जाता है जो उसे बुलाने वाली पक्ष के कहने पर सच बोलने का इच्छुक नहीं होता है और एक प्रतिकूल गवाह वह होता है जिसे किसी पक्ष द्वारा किसी विशेष विवादित तथ्य को साबित करने के लिए बुलाया जाता है या जो विवाद्यक से सुसंगत होता है, ऐसे तथ्य को साबित करने में विफल रहता है, या विपरीत परीक्षण साबित करता है। भारत में गवाहों को बुलाने वाले पक्ष द्वारा उनसे जिरह करने का अधिकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। धारा 142 के अनुसार गवाह से सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना मुख्य परीक्षण या पुन: परीक्षण में नहीं पूछे जा सकते। हालाँकि, न्यायालय उन मामलों के बारे में सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकती है जो परिचयात्मक या निर्विवाद हैं या जो, उसकी राय में, पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं। धारा 154 न्यायालय को विवेकाधिकार देता है कि वह गवाह को बुलाने वाले व्यक्ति को उससे ऐसा कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति दे, जिसे विरोधी पक्ष द्वारा प्रति–परीक्षण में पूछा जाता है। इसलिए, न्यायालयों का यह विधिक दायित्व है कि वे अपने विवेक का प्रयोग न्यायपूर्ण तरीके से विवेक का उचित उपयोग करके और उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करें। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत प्रति–परीक्षण की अनुमति केवल गवाह को बुलाने वाले पक्ष के पूछने पर नहीं दी जा सकती और न ही दी जानी चाहिए। सत पॉल बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR (1976) SC 294 में इस न्यायालय ने "पक्षद्रोही, प्रतिकूल

और प्रतिकूल गवाहों" शब्दावली और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए धारित किया कि: "अर्थ पर विवाद से बचने के लिए 'पक्षद्रोही' गवाह, 'प्रतिकूल' गवाह, 'प्रतिकूल' गवाह जैसे शब्दों के कारण, जिन्होंने इंग्लैंड में काफी कठिनाई और विचारों के टकराव को जन्म दिया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के लेखकों ने सलाह दी है कि इनमें से किसी का भी उपयोग न किया जाए। ताकि, भारत में, किसी पक्ष द्वारा अपने ही गवाह से जिरह करने की अनुमति देना, गवाह को 'प्रतिकूल' या 'पक्षद्रोही' घोषित किए जाने पर सशर्त न हो। चाहे वह धारा 142 के तहत सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति देना हो, या धारा 154 के तहत उन प्रश्नों को पूछने की अनुमति देंना हो जिन्हें विरोधी पक्ष द्वारा जिरह में पूछा जा सकता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस मामले को पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर छोड़ देता है (बैकुंठ नाथ बनाम प्रसन्नमयी AIR (1922) PC 409 में सर लॉरेंस जेनकिंस की टिप्पणियों को देखें)। धारा 154 द्वारा न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधिकार अप्रतिबंधित और अनियंत्रित है, और 'पक्षद्रोहिता' के किसी भी प्रश्न से अलग है। इसका उदारतापूर्वक प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब न्यायालय गवाह के भावभंगिमा, स्वभाव, दृष्टिकोण, व्यवहार, या उसके उत्तरों की प्रकृति और प्रवृत्ति से, या उसके पिछले असंगत बयान के अवलोकन से, या अन्यथा, यह सोचती है कि ऐसी अनुमति देने से सत्य उजागर होगा और न्याय करना समीचीन होगा। ऐसी अनुमति देना गवाह की सत्यता के संबंध में न्यायालय द्वारा निर्णय के समान नहीं है। इसलिए, ऐसी अनुमति देने वाले आदेश में, 'पक्षद्रोही घोषित', 'प्रतिकूल घोषित' जैसी ऐसी अभिव्यक्तियों के उपयोग से बचना बेहतर है, जिनका महत्व अभी भी ऐतिहासिक मकड़जाल से मुक्त नहीं है, जो उनके मद्देनजर लाता है भ्रम और संघर्ष की एक भ्रामक विरासत जिसने लंबे समय से अंग्रेजी न्यायालयों को परेशान कर रखा था।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी पक्ष द्वारा अपने ही गवाह की जिरह और विरोधाभास के संबंध में अंग्रेजी विधि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निहित कानून से भौतिक रूप से भिन्न है। अंग्रेजी विधि के तहत, किसी पक्ष को अपने ही साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप करने के लिए बुरा चरित्र, संदिग्ध पूर्ववृत्त या पूर्व दोषसिद्धि के सामान्य साक्ष्य को अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत में धारा 155 के तहत न्यायालय की सहमति से ऐसा किया जा सकता है। 1865 के अंग्रेजी अधिनियम के तहत , गवाह को बुलाने वाला पक्ष न्यायालय की इजाजत से गवाह से उसके पिछले असंगत बयानों के संबंध में 'जिरह' और खंडन तभी कर सकता है, जब न्यायालय गवाह को 'प्रतिकूल' मानती हो। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 और 155 में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है और ऐसी अनुमति देना पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिसका प्रयोग न्यायालय द्वारा साक्षी की 'पक्षद्रोहिता' या 'प्रतिकूलता' पर निर्भर नहीं है। इस संबंध में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंग्रेजी विधि से आगे है। इंग्लैंड की आपराधिक कानून संशोधन समिति ने हाल ही में बनाई गई अपनी 11 वीं रिपोर्ट में, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1865 की धारा 3 के आधुनिक संस्करण को अपनाने की सिफारिश की है, जिसमें प्रतिकूल और पक्षद्रोही दोनों गवाहों को बिना न्यायालय की अनुमति के अन्य सबूतों के साथ खण्डन की अनुमति दी गई है। हालाँकि, रिपोर्ट अभी भी

किसी पक्ष द्वारा अपने ही गवाह की विश्वसनीयता पर उसके बुरे चरित्र के आधार पर अधिक्षेप पर रोक बरकरार रखने के पक्ष में है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए प्राचीन अंग्रेजी निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को उचित समझ के बिना धारित करने के खतरे को कई आधिकारिक घोषणाओं में इंगित किया गया है। प्रफुल्ल कुमार सरकार बनाम सम्राट, ILR 58 Cal 1404 = (AIR 1931 Cal. 401)(FB) में एक प्रख्यात मुख्य न्यायाधीश, सर जॉर्ज रैंकिन ने चेतावनी दी थी, कि 'जब हमें अंग्रेजी न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आदेशों को याद करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, प्रख्यात, उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, सावधान रहना आवश्यक था कि कहीं ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत न कर दिए जाएं जिन्हें भारतीय विधानमंडल ने अधिनियमित करना उचित नहीं समझा।' इस बात पर जोर दिया गया कि अंग्रेजी कानून से इन विचलनों को 'या तो स्वयं में सुधार के रूप में लिया गया या भारतीय परिस्थितियों में बेहतर काम करने के लिए गणना की गई।'

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से, यह स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक अभियोजन में भी जब एक गवाह से प्रतिपरीक्षण की जाती है और न्यायालय की अनुमति से पक्ष द्वारा उसका खंडन किया जाता है, तो उसके साक्ष्य को कानून के मामले के रूप में नहीं माना जाता बल्कि उसे रिकॉर्ड को पूरी तरह से मिटाने के रुप मे माना जाता है। प्रत्येक मामले में यह विचार करना न्यायाधीश का काम है कि क्या इस तरह का प्रतिपरीक्षण और खण्डन के परिणामस्वरूप, गवाह पूरी तरह से विश्वसनीयता खो दिया या उसकी गवाही के एक हिस्से के संबंध में अभी भी उस पर विश्वास किया जा सकता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि इस प्रक्रिया में, गवाह की विश्वसनीयता को पूरी तरह से खतम नहीं किया है, तो वह पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ, गवाह के साक्ष्य को पढ़ने और विचार करने के बाद, रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूत, उसकी गवाही का वह हिस्सा जिसे वह विश्वसनीय मानता है,के आलोक में स्वीकार कर सकता है और उस पर कार्रवाई करेगा। यदि किसी दिए गए मामले में, गवाह की पूरी गवाही पर सवाल उठाया जाता है, और इस प्रक्रिया में, गवाह पूरी तरह से विश्वसनीय खो देता है, तो न्यायाधीश को विवेक के तौर पर, उसकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए।"

हम उस तरीके की निंदा करते हैं जिसमें लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना की गई थी और विचारण न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह (पीडब्लू 2) से कथित तौर पर उसके पक्षद्रोही होने के आधार पर प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। तथ्यों पर हमने पाया कि उक्त गवाह को गलत तरीके से प्रतिपरीक्षण की अनुमति दी गई थी। यह केवल घटना के बाद के विवरण पर था, वह लोक अभियोजक द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत नहीं थे। हमारी राय में, वह एक बिंदु, लोक अभियोजक के लिए यह घोषित करने के लिए बहुत अपर्याप्त था कि गवाह ने पलटवार किया और अभियोजन पक्ष के प्रति पूरी तरह से प्रतिकूल हो गया। अन्यथा भी जिरह के लिए दी गई और उपयोग की गई अनुमति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय की सीमा तक ही सीमित थी (प्रदर्श पी–2)। साक्षी संख्या 2 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जो अपीलकर्ता से निकटता से जुड़ा हुआ है और उसके पास झूठा फंसाने

का कोई कारण नहीं है, खासकर जब कोई प्रलोभन, धमकी, वादा या आश्वासन कथित तौर पर नहीं दिया गया हो। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि साक्षी संख्या 5 और 7 की गवाही के अभाव में भी यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि अपीलकर्ता ने अनुचित प्रभाव, दबाव, वादे या प्रलोभन के बिना साक्षी संख्या 2 और 6 के समक्ष स्वैच्छिक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी। ऐसा बयान अपीलकर्ता द्वारा घटना के तुरंत बाद उन गवाहों के समक्ष दिया गया था जो स्वतंत्र और विश्वसनीय हैं। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खून से सने चादर और अपराध में प्रयोग किये गये हथियार कस्सी की बरामदगी उसके द्वारा दिए गए स्वैच्छिक प्रकटीकरण बयानों के आधार पर की और इसे सभी संदेहों से परे साबित कर दिया है। शंभू सिंह (साक्षी संख्या 12) ने गिरफ्तारी ज्ञापन के बाद(प्रदर्श पी–14) कहा है कि अपीलकर्ता के जूते मानव खून से सने थे जो जप्त कर लिए गए और उनकी सूचना पर कस्सी (प्रदर्श पी–21) (अनुच्छेद ए–1) को उसके घर के अंदर से बरामद किया गया। बरामदगी को अनुसंधानकर्ता (साक्षी संख्या 2) के अलावा निरंजन सिंह (साक्षी संख्या 6) और जोगिंदर सिंह (साक्षी संख्या 7) की गवाही से साबित किया गया। 12 जुलाई, 1976 को अपीलकर्ता ने चादर के बारे में जानकारी दी, जिसे प्रदर्श पी–22 के रूप में दर्ज किया गया था और राम सिंह, (साक्षी संख्या 3) की उपस्थिति में उसने वही चादर पेश की, जो उसने अपने घर में एक घड़े(मिट्टी का पानी का बर्तन) में छिपाकर रखी थी। जब्ती सूची राम सिंह (साक्षी संख्या 3), जरनैल सिंह (साक्षी संख्या 2) और शंभू सिंह (साक्षी संख्या 12) द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया गया था। चादर इंसानों के खून से सना हुआ था।दोनों ही विचारण, साथ ही उच्च न्यायालय ने सही माना कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता द्वारा प्रकटीकरण बयान देने और उसके निशानदेही पर अपराध के हथियार और चादर की बरामदगी को साबित करने में सफल रहा है। प्रकटीकरण बयान देने के बाद आरोपी की निशानदेही पर अपराध के हथियार कस्सी में एक बाल पाया गया, जिसे बरामद किया गया। जांच एजेंसी ने मृतक की खोपड़ी और खोपड़ी के बाल भी जप्त कर लिए, तीनों बालों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया , जहां मॉर्फोलॉजिकल परीक्षण के बाद पता चला कि सभी बाल मानव सिर के हैं। चादर (शीट), पगड़ी, जूते की जोड़ी, कस्सी जैसे कई अन्य सामान भी विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए थे। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया– "रक्त को प्रदर्श संख्या 1, 2 (जो '1' चिन्ह से चिह्नित पैकेट से), 3, 4 ('2' से), 5 ('4' से), 7 ('6' से), 8 ('7' से), 9 ('8' से) और 10 ('9' से) में पाया गया।

खून से सने हुए कटिंग/नमूने उनके संबंधित नियंत्रणों के साथ, जहां भी उपलब्ध हों, सीरोलॉजिकल जांच के लिए सीरोलॉजिस्ट को भेज दिए गए हैं।

प्रदर्श संख्या 5 ('4' से) और 6 ('5' से) के नमूने मिट्टी की जांच के लिए भौतिकी विभाग को भेज दिए गए हैं।

प्रदर्श संख्या 10 ('9' से) को सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए सीरोलॉजिस्ट के पास भेज दिया गया है।"

भारत सरकार के सीरोलॉजिस्ट और केमिकल परीक्षक ने चादर और अन्य वस्तुओं को मानव रक्त से सना हुआ पाया। हालाँकि, वस्तुओं, जूतों की जोड़ी और कस्सी पर खून के धब्बों की उत्पत्ति समय बीतने के साथ विघटन के कारण निर्धारित नहीं की जा सकी। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि रक्त की उत्पत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सका , इसलिए अपीलकर्ता बरी किए जाने का हकदार है, क्योंकि उनके अनुसार अभियोजन पक्ष आरोपी को अपराध से जोड़ने में विफल रहा है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने प्रभु बाबाजी नवले बनाम बॉम्बे राज्य [एआईआर 1956 एससी 51], राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1963 एससी 74], शंकरलाल ग्यारसीलाल दीक्षित बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य [1981 (2) एससीआर 384], कंसा बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य [एआईआर 1987 एससी 1507]। प्रभु बाबाजी और राघव प्रपन्न त्रिपाठी के मामलों में निर्णयों के आलोक में रक्त के विघटन के कारण रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में सीरोलॉजिस्ट की विफलता के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य में विचार किया गया था । [1999 (3) एससीसी 507] जिसमें कहा गया था: "इस बीच सीरम के विघटन के कारण रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में सीरोलॉजिस्ट की विफलता का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कुल्हाड़ी पर चिपका हुआ रक्त मानव रक्त नहीं होगा। कभी –कभी ऐसा होता है, या तो दाग बहुत अपर्याप्त होने के कारण या हेमेटोलॉजिकल परिवर्तनों और प्लास्मेटिक जमावट के कारण, एक सीरोलॉजिस्ट रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफल हो सकता है। क्या इसका मतलब यह होगा कि रक्त किसी अन्य मूल का होगा? ऐसे यह अनुमान लगाना कि दूसरी कुल्हाड़ी पर लगा खून जानवरों का खून होगा, इस मामले के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अवास्तविक और दूर की कौड़ी है। आपराधिक अदालत का प्रयास कल्पनाशील संदेहों की तलाश में नहीं जाना चाहिए। जब तक कि संदेह उचित आयाम का न हो न्यायिक रूप से कर्तव्यनिष्ठ दिमाग कुछ निष्पक्षता के साथ मनोरंजन करता है, आरोपी द्वारा किसी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त साक्ष्यों की अस्वीकृति को बनाए रखने का प्रयास किया , जिसके लिए उन्होंने प्रभु बाबाजी नवले बनाम बॉम्बे राज्य [एआईआर 1956 एससी 51] और राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम यूपी राज्य के निर्णयों का हवाला दिया । [एआईआर 1963 एससी 74]। पूर्व में, विवियन बोस, जे. ने देखा है कि रासायनिक परीक्षक का कर्तव्य प्रत्येक प्रदर्शन पर उसके द्वारा पाए गए खून के धब्बों की संख्या और प्रत्येक दाग की सीमा को इंगित करना है, जब तक कि वे विस्तार से वर्णित करने के लिए बहुत छोटे या बहुत अधिक न हों। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई एक धोती पर खून का सिर्फ एक धब्बा थी। उनके आधिपत्य ने महसूस किया कि "हमारे द्वारा पहले फैसले में वर्णित परिस्थितियों में गुजरने वाले एक पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति की धोती पर भी खून समान रूप से बह सकता था"। बाद के फैसले में, इस न्यायालय ने एक रासायनिक परीक्षक के प्रमाण पत्र के संबंध में कहा कि यद्यपि खून का धब्बा मानव मूल का साबित नहीं हुआ है , लेकिन 'परिस्थितियों में' आरोपी को हत्या से जोड़ने का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। उस मामले में परिस्थितियों

के आगे के भाग से पता चला कि एक शर्ट को ड्राईक्लीनिंग प्रतिष्ठान से जब्त किया गया था और उक्त प्रतिष्ठान के मालिक ने गवाही दी थी कि जब शर्ट उसे ड्राईक्लीनिंग के लिए दी गई थी, तो उस पर खून का धब्बा नहीं था।

हम उपरोक्त निर्णयों से किसी भी कानूनी अनुपात का पता लगाने में असमर्थ हैं कि उन सभी मामलों में जहां रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफलता हुई थी, हथियार की बरामदगी से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को अनुपयोगी माना जाएगा। उपरोक्त मामलों में टिप्पणियाँ वहां मौजूद तथ्यात्मक स्थिति पर की गई थीं। उन्हें ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता जहां तथ्य भौतिक रूप से भिन्न हों।"

तेजा राम के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर, हमें अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों में ऐसाकोई तथ्य नहीं मिला कि रक्त की उत्पत्ति के संबंध में रिपोर्ट के अभाव में, विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। सीरोलॉजिस्ट और रासायनिक परीक्षक ने पाया है कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के परिणामस्वरूप जप्त की गई चादर मानव रक्त से सना हुआ था। चूंकि समय बीतने के साथ रक्त का वर्गीकरण निर्धारित नहीं किया जा सका, इसलिए इस तरह के विलंबित और बासी तर्क के बल पर किसी भी लाभ का दावा करने के लिए आरोपी को कोई बोनस नहीं दिया जाता है। इसलिए, विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय का भी इस परिस्थिति को अपीलकर्ता के खिलाफ संदेह से परे साबित मानना उचित था।

चादर और अन्य वस्तुओं पर खून के धब्बों के आयामों का उल्लेख न करने का लाभ उठाते हुए और कंस बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य [एआईआर 1987 एससी 1507] में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि ऐसी विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है और कथित तौर पर उसके खिलाफ साबित हुई परिस्थितियों की श्रृंखला में एक लापता कड़ी है। उपरोक्त तर्क वर्तमान मामले में आरोपी–अपीलकर्ता के लिए कोई मददगार नहीं हुआ। कंस बेहरा के मामले (सुप्रा) में, अभियोजन पक्ष का आरोप था कि मृतक का जीतराई माझी नामक व्यक्ति के साथ कुछ विवाद था और वह भाई हैं। जीतराई माझी पर आरोप था कि उसने कंस बेहरा की मदद से मृतक की हत्या करायी है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष का मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया उनमें से एक यह थी कि जब अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके कब्जे से बरामद धोती और शर्ट मानव रक्त से सने हुए पाए गए थे। उस संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा: "किसी व्यक्ति के कपड़ों पर कुछ छोटे खून के धब्बे उसके अपने खून के भी हो सकते हैं, खासकर अगर वह कोई ग्रामीण है जो इन कपड़ों को पहनता है और गांवों में रहता है। रक्त समूह के बारे में सबूत, खून के धब्बों को मृतक से जोड़ने के लिए केवल निर्णायक हैं। वह सबूत अनुपस्थित है और मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय में, यह ऐसी परिस्थिति भी नहीं है जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।"

वर्तमान मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है क्योंकि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की तारीख से लगभग 5 दिनों के बाद खून से सनी चादर बरामद की गई थी, जिसे उसने एक घड़े में छिपाकर अपने घर में रखा था। लेकिन अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के अनुसार, उसकी चादर पर खून के धब्बे होने का तथ्य सामने नहीं आया। गौरतलब है कि मामले में टिप्पणी करने से पहले कोर्ट ने कहा था कि जहां तक शर्ट और धोती की बरामदगी का सवाल है, तो यह बताने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि आरोपी ने घटना के समय ये कपड़े पहने हुए थे।

कंस बेहरा के मामले में की गई टिप्पणियाँ केवल उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित थीं और सभी मामलों पर सार्वभौमिक रूप से लागू करने का आशय नहीं था। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में खून के धब्बों के आयामों की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यदि जप्ती सूची में सीमा का उल्लेख किया गया है तो इसकी सराहना की जाएगी, लेकिन जब्ती सूची में इसका विवरण देने में विफलता आरोपी को केवल उस आधार पर अभियोजन मामले को अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं देगी। खून के धब्बों के आयामों का उल्लेख न करना शायद उन मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है जहां अभियुक्त बचाव की मांग करता है या आरोप लगाता है कि अभियोजन पक्ष दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपराध कारित करने में उसे फंसाने के लिए साक्ष्य गढ़ा है। ऐसी परिस्थिति की विश्वसनीयता को केवल कपड़ों पर खून के धब्बों के आयामों का उल्लेख न करने से कमजोर नहीं किया जा सकता है , खासकर तब जब अभियोजन के मामले पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की ओर इशारा नहीं किया गया हो। केवल खून के धब्बों के आयामों का उल्लेख न करने पर उत्पन्न हुआ संदेह अपनेआप में अभियुक्त को संदेह का लाभ पाने का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मामले में, हमने पाया है कि यह परिस्थितियाँ पूरी तरह से साबित है और जहां तक अभियुक्त द्वारा अपराध करने का सवाल है, कोई संदेह पैदा नहीं करता है, उचित संदेह तो बिल्कुल भी नहीं पैदा करता है।

हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता ने पीडब्लू 2 और 6 को स्वैच्छिक प्रकटीकरण बयान दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अपराध के हथियार और चादर की बरामदगी हुई थी, जिसे उसने अपने घर में छुपाया था, कस्सी पर लगे बाल की तुलना मृतक के शरीर से लिए गए बालों से की गई और विश्लेषण करने पर पाया गया कि वह मानव बाल थे और उसकी चादर मानव रक्त से सना हुआ था। उपरोक्त परिस्थितियाँ अभियुक्त को उस अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त थीं जिसके लिए उसे विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जिसकी संपुष्टि उच्च न्यायालय ने की। अपील में कोई बल नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

अनुवादित :– अर्चना मिश्रा